NEWSLETTER OF FINANCE & ECONOMICS THINK COUNCIL

The Enquiry

AN INSIGHT INTO POLICY AND GOVERNANCE

VOL-01
ISSUE-01
AUG-SEP ISSUE

INSIGHT

सरकार मजबूत है पर आंकड़े कमजोर हैं ।

Ayushman Bharat- A leaking missile for India's health sector

KUMBHA MELA : DEVOTION TO DISCIPLINE

क्या बैंको के विलय से सुधरेंगे इनके मौजूदा हालात?

A cut in excise duty on petrol and diesel - Expedient or Inexpedient

NDA government's determination for financial inclusion

Weak Rupee, High Oil Prices: Cause and Effect

Indian Rupee crashing below 73 against the US Dollar for the first time.

US Sanction toward oil supplies from Iran ballooned the crude oil prices extending a bullish view toward crude oil future ranging around 68 to 72 dollars. Increasing tension between the world's two largest economies – US and China – has kept the investor on the edge amidst fears of global trade war.

Another catalyst to the situation is the uprise in the US's GDP which grew by 4.1% in the second quarter of 2018, fastest since late 2014. Foreign Institutional Investors(FII) have sold debt and equity with value of more than Rs. 40,000 crores so far this year. A wider current account deficit and continuous outflow from FIIs has pushed the currency lower.

The hike in the oil prices alongside weakening rupee conveys an upshot of CAD from 1.9% last year to 2.8% of GDP this financial year. It is perceptible that a high CAD can create macroeconomic vulnerability in an economy, specifically affecting stability in currency markets.

CONCLUSION: To avoid falling in the muddled situation as in 2013, government must act on its foes to strengthen the situation. There should be an intervention by the RBI in the present situation to maintain inflation while keeping in mind the economic growth.

अर्थनीति

सरकार मजबूत है पर आंकड़े कमजोर है।

विक्रांत सिंह

सरकार मजबूत है पर रुपया कमजोर है। आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ है पर बैंकों की हालत गंभीर है। वर्तमान केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां मजबूत है पर तेल के दाम आसमान छू रहे है। सरकार ने रोजगार पैदा किए हैं पर आंकड़े बनाना भूल गई है। ऐसे तमाम तर्क है जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिए जा सकते हैं। असल में अर्थव्यवस्था चलाना बिल्कुल उस पार्ले बिस्किट की तरह होता है जो कुछ सेकंड देरी की वजह से चाय में ही गल कर खत्म हो जाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था को एक संवेदनशील व्यवस्था कहा गया है।

वर्तमान समय में तेल के दाम आसमान छू रहे और रुपया अपने निम्न स्तर को प्राप्त कर चुका है। यह संकेत कहीं से भी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अच्छा तो नहीं दिखता है। पर सरकार इस पर चुप है और बाह्य कारणों का हवाला देकर इन मुद्दों से हट रही है। याद रखिए सरकार मजबूत है। बस मजबूत सरकार की परिभाषा बदल गई है। वैसे सरकार की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन रोजगार, किसान एवं बैंकिंग के आधार पर बांट कर किया जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों से रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और रोजगार के आंकड़ों को लेकर देश में एक नए तरह के बहस को देखा गया। जहां सरकार और विपक्ष के दावे अलग थे। सरकार ने प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार को लेकर दावे पेश किए। सरकार ने अप्रत्यक्ष रोजगार आंकड़ों को लेकर पकौड़ा से शुरुआत कर पान वाले तक पहुंच कर रोजगार की परिभाषा तय की। हां यह रोजगार है पर कौन से और किसके लिए ? देश में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी के बीच ऐसी तर्क कैसे तर्कसंगत हो जाते हैं ? हाल ही में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सतत रोज़गार केंद्र ने एक रिपार्ट जारी की है और यह अध्ययन स्टेट आॅफ वर्किंग इंडिया (एसडब्ल्यूआई) की ओर से किया गया है। हफिंग्टन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 20 वर्षों में भारत में बेरोज़गारी दर सबसे ज्यादा देखी गई है। नौकरियों की यह कमी निराशाजनक वेतनमान से बढ़ी है। 82 प्रतिशत पुरुष और 92 प्रतिशत महिलाएं प्रति माह 10,000 रुपये से भी कम कमा पा रहे हैं। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है, 'पारंपरिक रूप से भारत में बेरोज़गारी नहीं बल्कि अंडर एंप्लॉयमेंट और कम मजदूरी समस्या थी। उच्च शिक्षा प्राप्त और युवाओं में बेरोज़गारी 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऐसी गंभीर परिस्थिति में पकौड़ा और ऑटो कैसे सही साबित होते हैं इस पर प्रश्न पूछना होगा ?

खैर रोजगार के आंकड़ों में सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना रही उस पर चर्चा करना जरूरी है। सरकार ने दावा किया है कि मुद्रा योजना के जरिए रोजगार उत्पन्न किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त 2018 तक बैंकों द्वारा कुल 13,37,85,649 कर्ज दिए गए जिनकी कुल राशि 6,32,383 करोड रुपए थी। अगर इस दिए गए मुद्रा कर्ज के अवसर की बात करें तो प्रति कर्ज औसत ₹47268 का बनता है। सरकार को बताना होगा कि ₹47268 में किस तरीके के रोजगार पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि एक मुद्रा लोन एक रोजगार के बराबर है इस हिसाब से सरकार ने अभी तक तकरीबन 14 करोड़ रोजगार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न किए हैं। इस तर्क से 2 करोड़ रोजगार देने के दावे को सरकार ने पूरा किया है और देश में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। असल में देश इस समय रोजगार मंदी की तरफ बढ़ रहा है जो एक बड़े विस्फोट के रूप में सामने आने वाला है।

सरकार की आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन करने का दूसरा पहलू किसानों की समस्या एवं उनके समाधान को लेकर देखा जा सकता है। पिछले 4 वर्षों में किसान सरकार से संतुष्ट नजर नहीं आए। किसानों की नाराजगी के पीछे सरकार के लिए सरकार के आंकडे ही संकट पैदा कर रहे हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 31 मई 2018 को कृषि वृद्धि दर पर आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार कृषि विकास दर 2.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4.9 प्रतिशत से काफी कम थी। आर्थिक सर्वेक्षण-2018 की रिपोर्ट कहती है कि कृषि आय पिछले 4 वर्षों में महज 1.9% की दर से बढ़ी है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दर से किसानों की आय दोगुनी करने में इतना समय लग सकता है ? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो कि एक बड़े अर्थशास्त्री भी हैं उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमें 14% की दर से किसानों की आय में बढ़ोतरी करनी होगी। अब आंकड़ों के हिसाब से मोदी जी के दोगुनी आय के सपने में मजबूती तो नहीं दिखती है। सरकार ने किसानों के प्रति बिगड़ती छवि को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करने की मंजूरी भी कैबिनेट के जरिए की। धान के समर्थन मूल्य में ₹200 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1550 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1750 रुपए कर दिया गया। यूपीए-1 ने भी सन् 2008-09 में 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का कुछ ऐसा ही दावा किया था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बावजूद भी किसान एवं किसान संगठन अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे है। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसलों के दाम सीटू यानी कि कंप्रीहेंशन कास्ट प्रणाली के अनुसार तय होने चाहिए। सीटू प्रणाली के अनुसार इनपुट की लागत, फैमिली लेबर, जमीन का रेंट और पूंजी पर ब्याज शामिल करने के बाद फसलों की कीमत तय की जाती है। किसानों का कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने ए टू प्लस फैमिली लेबर जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार किया है जो कि किसानों के साथ एक ऐतिहासिक धोखा है।

तीसरा और प्रमुख आर्थिक पैमाना बैंकिंग सिस्टम को लेकर देखा जा सकता है। वर्तमान समय में बैंकिंग सिस्टम एनपीए जैसे गंभीर मुद्दे को देख रहा है। पिछले 4 वर्षों में एनपीए(नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) चौगुनी रफ्तार से बढ़ी है। पब्लिक सेक्टर बैंक जिनका एनपीए 2014 में 2,16,739 करोड़ रुपए था जो कि 31 मार्च 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार 8,45,475 करोड़ रुपए हो गया है। बैंकों की बिगड़ती वर्तमान स्थिति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2017-18 में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने कुल 85,370 करोड रुपए का नुकसान दर्ज किया। इन पब्लिक सेक्टर बैंकों में सिर्फ दो ऐसे बैंक रहे जिन्होंने लाभ अर्जित किया है। विजया बैंक ने 727 करोड रुपए और इंडियन बैंक में 1259 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए किसकी जिम्मेदारी तय नहीं चाहिए ? वर्तमान केंद्र सरकार की या पुराने 70 साल के इतिहास की।

देश की वर्तमान विकास दर 8% से अधिक की है लेकिन प्रश्न आज भी मौजूद है कि आर्थिक असमानता इतनी अधिक क्यों ? हम एक ही साथ दो भारत देखते हैं इनके बीच में अब खाई बढ़ती जा रही है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय दर में भारत 126 में स्थान पर आता है तो फिर इस विकास दर के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय दर क्यों नहीं बढ़ रही है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास के शोर में ऐसे प्रश्न कहीं छिप जा रहे हैं ?

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आर्थिक मुद्दे तेजी से जगह लेते हैं। रोजगार, एनपीए, किसान और तेल के बढ़ते दामों के बीच अब राफेल ने भी अपनी उड़ान भर ली है। उम्मीद है कि राफेल की गर्जन 2019 के चुनाव के बाद भी सुनाई देगी। देश इसकी सच्चाई जान पाएगा।

Healthcare

Ayushman Bharat – a Leaking Missile for India's Health Sector

Anand Mishra

The prosperity of any country depends on how healthy and happy its citizens are. In a developing country like India, improvement in the level of healthcare services should be one of the top parameters of development. Although India is continuously increasing its recognition in the eyes of the world on the economic barometer, a major section of our country is still lagging behind on the front of holistic social development. People are suffering from such diseases upon which a considerable portion of income has to be spent, which further downgrades their standard of living. It is easier for economically sound families to get themselves treated even at sky-rocketing charges in private hospitals. But the families which can barely earn livelihood for survival, often surrender in case of disease to any of its members before large queue outside public hospitals and due to numerous official formalities and high priced medicines in the market.

To cater to above problems, an announcement was made regarding a universal health protection scheme called 'Ayushman Bharat' on 14th April, 2018. To mark the completion of 71 years of independence, Prime Minister Narendra Modi outlined in his Independence Day speech the details of the scheme. On 23rd Sept, 2018 the scheme has officially been gifted for the public welfare from Ranchi, Jharkhand. There are two aspects of Ayushman Bharat:

1. Development of adequate Health & Wellness Centers.

2. National Health Protection Scheme (Jan Arogya Yojana)

As per the plans about 1.5 lakh health & wellness centers would be developed by the year 2022, to make the basic and primary health services accessible to the last person in the queue with minimal difficulties. These shall provide free essential drugs and diagnosis. For this, ₹1200 crores would be allocated from the budget.

The other aspect of the scheme, Jan Arogya Yojana is touted to be the biggest state-funded scheme of its kind in the world. It is expected to cover poorest 40% of the Indian population. Around 10.74 crore families i.e. 50 crore people are to be covered under a family floater health insurance policy cover of ₹5 lakh per family per annum for secondary and tertiary health care. Out of these, 8 crore families from rural and 2 crore families from urban areas would be the beneficiaries. Eligible person can avail treatment in all the public as well as the listed private hospital networks. As of now 7826 hospitals have been listed for the purpose, of which 47% are private hospitals. The scheme shall subsume Rashtriya Swasthya Bima Yojana of UPA Govt. 2008 which was giving ₹30,000 cover to 3.63 crore poor families and other such schemes. Annual premium per family is estimated to be ₹2000 which would be shared by Central and State Governments in the proportion of 60:40.Eligibility of membership has been defined as per the Socio-Economic Census, 2011.

The scheme offers 1354 medical and surgical packages under 25 specialities in which hospitalisation expenses, consultation fees, surgical equipment, procedure charges, implanting costs, medicines, diagnostic tests and patient food is covered. All the diseases are covered from the day one i.e. there is no waiting period for any pre-existing disease, which is one of the best clause compared to the insurance schemes in market.

Ayushman Bharat in itself is a high-flyer scheme before which there are some paramount challenges. Few of the challenges have been outlined below:

1. To develop 1.5 lakh health & wellness centers, only ₹1200 crores have been allocated which comes to only ₹80,000 per health center, which is not sufficient to satisfy the purpose. It is preposterous to even think of a health center in ₹80,000. For PMJAY (Jan Arogya Yojana), only ₹2000 crores have been set aside from the budget, whereas the estimated spending this year would be around ₹5000 crores and ₹10,000 crores from this year onward. Appropriate and sufficient budgetary allocation is a major concern for the successful implementation.

2. Centre has proposed for 40% partnership by state governments. To allocate such a major chunk from the budget would be very difficult for the states which are already facing budgetary deficit. Apart from that, various health insurance schemes are already operational in various states. Duplicating the allocation for same purpose would not be intelligent. Moreover, to bring onboard those State Governments which have differences with the Central Government would be a herculean task. It has come to information that five states i.e., Telangana, Odisha, Delhi, Kerala and Punjab have opted out from the scheme citing different reasons ranging from limited coverage of population to duplication of schemes to funding proportion.

3. Due to insufficient number of public hospitals, the success of scheme totally depends on the support from private hospitals. A big question about uniformity of charges for specific disease for all the private hospitals shall always remain valid. As compared to others, some high goodwill hospitals charge much more for treatment. A regulation in the same matter needs to be passed to avoid any discrepancies by private hospitals.

4. It is obvious that the government can't handle such a large scale health insurance scheme on its own. For actuarial database and operational purpose, it requires cooperation of leading companies in the sector. It is doubtful whether private companies would support public institutions at such low rate premium without any additional terms, conditions and clauses when actual premium rate is higher in market.

5. About 80% of Indian population is still not covered under any health insurance scheme even after 70 years of independence. According to a study, 3.7 to 4.5 per cent of total Indian GDP is required to be invested in health sector for total coverage, while only 1.4 per cent is being allocated to health sector currently.

The government needs to address all the above challenges at the earliest. Only then can the success of such an ambitious project be ensured. Earlier too, such healthcare schemes were initiated by many State Governments and the Central Government, but failed due to inadequate preparation and improper implementation.

Dharma

KUMBHA MELA – DEVOTION TO DISCIPLINE

Ayushi Dixit

***Kumbha* is the symbol of all that is and all that exists, *Kumbha* symbolizes life.**

An ageless carnival which has been commemorating the existence of humanity is '*Kumbha Mela*'. Since time immemorial *Kumbha Mela* has served as a rostrum to propagate and preserve the individual and collective faith of the cosmos, ascetic exhibitions of yogic performances, recitation of religious texts, trade and discourses on socio-religious problems.

The divine land of *Haridwar, Allahabad, Nashik and Ujjain* witness the ecstasy of *Kumbha Mela.* The receded mud, the majestic *ghats*, the glorious cities residing on the fringes of rivers – *Ganga (Haridwar), Triveni Sangam (Allahabad), Godavari (Nashik), Shipra (Ujjain)* amalgamate to edify a 'pop-up megacity'. This city, laid out on a grid, is constructed and deconstructed within a matter of days. The evanescent civilization is inclusive of all the fundamental prerequisites which includes sanitation, security, commute service, temporal infrastructure (bridges, pathways, helipads etc.), water supply, drainage, markets, supply of electricity etc.

Civilizations become myth. We refrain ourselves from believing in the sagas. Hundred years later we all will be a folklore to the toddlers, but we do exist, don't we?

"Mythologically" *Amrit* or the nectar of immortality, fell from a pot (Kumbh) carried by the goddess Mohini. She drew it away heavenwards from the demons who had tried to claim it. This battle in the pursuit of *Amrit* is said to have lasted twelve divine days, which is the equivalent of twelve human years; therefore, the Mela is celebrated every twelve years, staggered at each of the four sites in this cycle.

The observance of Kumbha Mela can be traced back to Matsya Puran which continues till eighth century when Adi Shankaracharya instituted regular gatherings of learned ascetics for discussions and debates in the world's largest human gathering.

Today Kumbha Mela is a potent forum for interdisciplinary research in a number of complementary fields. Public health, pilgrimage and religious studies, design and planning, business, engineering, governance, and technology converge at this mega festival.

This concept of pop-up megacity should be extended beyond the religious spheres and come up as a prototype for understanding the spatial, social, and logistical elements of the ephemeral civilization through interdisciplinary research. The upshot will allow the deployment of these systems in a variety of places and situations, in particular camps for refugees of war and natural disasters.

Past few decades have brought a distorted picture of the Kumbha Mela. Being perceived through western lenses, time and again it has been regarded as "exotic tourism", "source of pollution", "superstitious" and whatnot. The history has witnessed that the cultures which lost the rights to describe themselves have been easily destroyed.

Kumbha Mela is a living testimony of Indian civilization; a merger of spirituality, awareness and wisdom. It's a place where devotion meets knowledge, quest meets destiny, and humanity meets divinity. It is a celebration of the existence of 'Life' and life needs to be preserved.

बैंकिंग

क्या बैंको के विलय से सुधरेंगे इनके मौजूदा हालात?

विपिन विहारी राम त्रिपाठी

विश्व में सबसे तेज़ी से उभरने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था बैंको के विशालकाय गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) से प्रभावित होती जा रही है।केंद्र सरकार ने बैंको की वर्तमान स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों (देना बैंक, बैंक आफ बड़ोदा और विजया बैंक) का विलय करने के लिए बैंकिंग बोर्ड को अपना प्रस्ताव भेजा है। श्री राजीव कुमार (सचिव वित्तीय सेवा) ने दिनांक 17.09.18 को बताया कि सरकार ने बैंकिंग विलय के लिए विगत अक्टूबर में एक वैकल्पिक तंत्र गठित किया था, जिसमें वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल है। इन्हें बैंको की स्थिति का अवलोकन करने एवं इनके विलय-अनुमोदन की रूपरेखा तय करने के लिए नियुक्त किया गया था।

दरासल, पिछले कुछ सालों में एनपीए में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जिससे बैंको की वित्तीय स्थिति गम्भीर बन गयी है और इससे देश की आंतरिक एवं बाहरी आर्थिक नीतियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने इस विकट समस्या से उभरने के लिए देना बैंक, बैंक आफ बड़ोदा और विजया बैंक के विलय की तैयारी कर ली है। विलय के लिए इन तीनो बैंको के चयन के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि ये सभी बैंक सीबीएस के लिए इनफ़ोसिस के फिनेक्ल बैंकिंग सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करते है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार बैंको की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का यह तीसरा बड़ा क़दम है। इससे पहले सरकार ने 01 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक का विलय इसकी 5 सहयोगी और भारतीय महिला बैंक के साथ कर दिया था। इसके अतिरिक्त दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता लाकर सरकार ने काफ़ी हद तक जानबूझकर ऋण ना चुकाने वालों पर नकेल कसी है।

सरकार ने नरसिम्हा कमिटी-II की सिफ़ारिशों को आंशिक रूप से मानते हुए आर्थिक रूप से मज़बूत 2 राष्ट्रीयकृत बैंको का विलय 1 आर्थिक रूप से कमज़ोर बैंक से करने का प्रस्ताव भेजा है। अगर यह प्रस्ताव तीनो बैंको के बोर्ड स्वीकार कर लेते है तो यह बैंक एसबीआइ और एचडीएफसी बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।

अंतराष्ट्रीय दक्षता और व्यावसायिक विशेषता का उद्देश्य लेकर मेगा बैंक बनाने के इस प्रस्ताव को अगर स्वीकृति मिल जाती है तो नए बैंक की स्थिति कुछ ऐसी बनेगी-

कुल व्यवसाय - ₹14.82 ट्रिल्यन
कुल शाखायें- 9,489
कुल कर्मचारी- 85,675
नेट एनपीए- 5.71% (₹80,000 करोड़)
सीआरएआर- 12.25%
टियर-1 पूँजी- 9.32%

चूँकि जापान में 1990 से 2004 के बीच वृहदस्तर पर हुए बैंको के विलय से बहुत लाभ हुआ था, संभवत: इसी कारण भारत ने भी ऐसे प्रयोग किए है। लेकिन अगर हम निकटतम इतिहास पर नज़र डाले तो पता चलता है कि भारत ने विगत 15 वर्षों के अंदर 2 बार बैंको का विलय किया है। पहली बार 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और ओरीएंटल बैंक आफ़ कॉमर्स का और दूसरी बार 2017 में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंको के साथ। दोनो ही स्थितियों में बैंको का प्रदर्शन प्रतिकूल ही देखने को मिला।

विलय के लिए प्रस्तावित बैंको में देना बैंक और विजया बैंक पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दोनो ही बैंक मुख्यतः क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत रहते है। पिछले कुछ वर्षों में देना बैंक ने ऋण देते वक़्त उदार एवं लापरवाह नीतियों का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप इनके नेट एनपीए तेज़ी से बढ़ने लगे और रिज़र्व बैंक को इन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेवल-2 में रखना पड़ा है। वर्तमान में इनका एनपीए 11.04% हो गया है और वह वित्तीय वर्ष 2017 में ₹1,923.15 करोड़ का शुद्ध घाटा झेल रही है। वही विजया बैंक के शाखा प्रबन्धक नितिन भारती सिंह ने बताया कि विजया बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने एनपीए को नियंत्रित करते हुए 4.10% पर रोका हुआ है और वित्तीय वर्ष 2017 में ₹727.02 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाने में सफल रहा।

बैंको के विलय से होने वाले प्रमुख फ़ायदे-

1. नए बैंक के पास पर्याप्त पूँजी होगी जिससे वे व्यापारिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति दे सकते है।
2. संयुक्त बैलेन्स शीट एक मज़बूत आर्थिक और सतत स्थिति प्रदर्शित करेगी।
3. मेगा बैंक की भोगौलिक पहुँच बढ़ेगी जिससे प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक आधार और सौम्य सेवायें बढ़ेगा।
4. मानव संसाधन के उपयुक्त समायोजन से कार्यकारी कुशलता बढ़ेगी।
5. अंतराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें विशेष मान्यता और स्थान मिलेगा।
6. आवश्यक पूँजी और अन्य संसाधन होने के कारण प्रौद्योगिकी उन्नति के अनेक द्वार खुलेंगे।
7. रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की नीति का कार्यान्वयन सुनियोजित और कुशलता के साथ सम्भव होगा।
8. बड़े पैमाने पर नियुक्तिया, प्रशिक्षण और विज्ञापन करने से मितव्ययिता आएगी और बैंक में तरलता समायोजन बना रहेगा।

लेकिन अगर बैंको के विलय का गहन रूप से अध्यन करे तो पता चलता है की इससे देश में प्रत्यक्ष नुक़सान भी है-

1. बैंको के विलय होने से निश्चित ही अनेक शाखायें और एटीएम को बंद करना पड़ेगा, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
2. एक बैंक के विकराल एनपीए दूसरे बैंको की बैलेन्स शीट को प्रभावित करेगा।
3. मूडी की एक रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग बैंको के विभिन्न लक्ष्य, प्राथमिकताएँ और व्यापार नीति होती है। विलय के बाद इनमे हितसंघर्ष होने की संभावनायें प्रबल हो जाएँगी।
4. प्रत्येक बैंक की कार्यसंस्कृति भिन्न होती है। विलय के बाद भर्ती प्रक्रिया, स्थानांतरण नीति और वरिष्ठता क्रम को पूर्ण रूप से समायोजित करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी समय और अर्थ का व्यय होगा।
5. सहयोगी बैंको (कंसोर्टियम) के व्यापक विस्तार की संवभावनाए ना के बराबर हो जायेंगी।
6. बैंको के आकार बढ़ने से उनका व्यापार और संगठनात्मक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी काफ़ी लम्बा समय लगेगा।

बैंको के विलय की ख़बर के एक दिन बाद मंगलवार को देना बैंक के शेयरो में 20% की उछाल के साथ ₹19.10 दर्ज की गयी। जबकि विजया बैंक के शेयर में 5.7% गिरावट के साथ ₹56.40 हो गये और बैंक आफ बड़ोदा ने 16.03% की गिरावट के ₹113.45 हो गये। विशेषज्ञों की माने तो अगर बैंको के बोर्ड सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने और विलय की प्रक्रिया को कैबिनेट और संसद के माध्यम से पूरा करने में लगभग 6 महीने का समय लग जाएगा। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह फैसला मौजूदा बैंको की ख़स्ता हालत से सुधार लाएगा या फिर पूर्व की तरह एक असफल प्रयास बनकर रह जाएगा।

Indian Economy

A Cut in Excise Duty in Petrol and Diesel - Expedient or Inexpedient!

Ashutosh Yadav

India is the **world's third-largest consumer** of crude oil after the U.S. and China. India imports **82%of** its total crude oil requirement to meet its energy demands. Recently, the prices of crude oil, in particular, petrol and diesel have been sky high. Rather the prices have been hitting all-time high day by day. The rate of increase in the prices is so high that there are fears that it may touch Rs.100 (particularly in Mumbai). It has enraged the public. It is being used as a jacking by much opposition parties.

Reasons for the increase in the prices;

There are multifold reasons for the surge in the prices of the petrol and diesel. Some of the significant among them are-

- Fear of trade war; fear of a currency war; Fear of Fed Tapering; The turmoil created in countries like Turkey and Venezuela; The U.S. sanction on Iran; Increase in the international crude oil prices since last 1 year.

ABCD of Taxes/Duties in Petrol and Diesel

The pricing of the fuel in the country is based on the Dynamic Pricing Method. In simple terms. In other words, the retail prices of the petrol and diesel are determined on every day early morning at 6 a.m. Both i.e. Center government and state government impose taxes after the refinement of the crude oil. The difference between the taxes imposed by the Center and State governments is that central government charges tax on a flat rate basis on the other hand state government charges tax on ad valorem basis. The central government collects tax on petrol at a flat rate of Rs.19.48 and on diesel at the rate Rs.15.33. On the other hand, VAT charged by state governments varies state by state. On an average, it is around 30% on petrol and 25% on diesel.

Why the CG has requested SG to reduce VAT rates?

Since the prices of international crude oil are at surge, the reduction in VAT rate will not impact the revenue and it will remain higher. However, the State governments are reluctant in doing so. They are of the opinion that they are already under high pressure because of (1) their decreased revenue due to GST and; (2) the obligation of maintaining Fiscal Deficit.

CG, will-less Central Government has shown its reluctance for cutting down excise duty. The government argues that all the factors leading to an increase in the prices are external. Besides, the reduction in the duty will hit the government's revenue. The extent to which the government's revenue will be hit is huge, for instance, for every Rs.1 reduction in the excise duty will cut the government's revenue by whopping Rs.30000 crore! In addition, it will jeopardize the Fiscal Prudence i.e. good economics over good politics. Already MOODY has shown it is apprehension that Indian government might not be able to attain its fiscal target of 3.3%.

Should the government go for the cut?

Indian politics has, at every turn, been affected by populist measures. Good politics has always subjugated good economics. Opposition parties, backed by the middle class, demanding for a cut in the prices to stem the sharp rise in the prices. But as intent shown by the present government in its initial tenure that it will go for the fiscal target should be adhered to instead of going for a populist measure. It is imperative to be intact with the fiscal prudence especially in the current ball game or picture of uncertainty in the global economy. Apart from this, there are also secondary reasons not to go for a price cut; firstly, they are contaminating and already have converted many cities into death traps. Secondly, since they are non-renewable therefore need to be conserved and lastly, oil is already exceedingly biggest import item and threatens to rise further exponentially as India develops and urbanises. Therefore, it will be prudent for the government to wait instead of going for any populist measure.

Financial Inclusion

NDA Government's Determination for Financial Inclusion

Akhil Pandey

Current NDA government determination for financial inclusion is reflecting clearly. India witnessed drastic change for financial inclusion after joining of the office by Modi led government. Every scheme of government is directly or indirectly contributing to financial inclusion, which has not been done before on such a mass level. Before proceeding, it is better to know about financial inclusion. Financial inclusion means to make beneficiary large population of unbanked society and rendering them services ranging from opening of accounts to access to formal credit system. It is also evident government endless effort and implementation system has helped to have account to most deprived person of society. It is not about just opening of bank accounts. It also, about how effectively these people uses banking services specially making benefit of formal credit like KCC or MUDRA.

According to World Bank global index data 80% of Indian adult now have bank account, which is being celebrated as the success of pmjdy. While the increase in proportion of adults having bank account is indeed impressive, 48 percent of those who have an account in financial institutions made no withdrawal or deposit in past 1 year. It shows threatening data.

Modi government has launched lot of scheme ranging from sukanya samridhi yojana to recently launched IPPB to give big push to concept of financial inclusion in economy. Considering PMJDY scheme, 32.41 crore accounts has been opened so far and 81224.5 crore has been received in these accounts. Jan Dhan Yojana helped to reduce dependence of rural people on moneylender but PMJDY scheme did not fully achieved objective for what it was launched rather it promoted duplication of accounts which directly represent wrong data. There are many non-functional accounts, which are wasteful burden on banks and increasing operational cost of banks. Government need to address this issue if it wants to achieve full financial inclusion in economy.

Now taking MUDRA Yojana , we can say that it has proved boon so far for many individuals who have vision of own business and employing other people. 6.37 lakh crore has been disbursed under this scheme by public and private sector bank, regional rural bank and micro finance institutions until date.

It brought drastic change in MSME sector regarding credit dependence. It is not hard anymore to get credit in MSME sector. Mudra Yojana worked very efficiently in direction of bringing small financial entrepreneurs into formal credit system. For this work done by government we must appreciate work done by NDA government, not only individuals but also self-help group also growing with help of mudra Yojana.

keeping in mind role of MSME sector which may solve controversial problem of employment in country, government targeted it very well for financial inclusion, but no need to be more optimistic once again regarding growth of MSME rather government should establish effective monitoring system for checking whether the loans are not going to be part of NPA, as warning signal given by Raghuram Rajan. However, PMMY also puts in place MUDRA bank, which monitors the network of microfinance institutions and helps to register new institutions as well recently launched IPPB will fulfil bottlenecks of PMJDY, who are still deprived of banking system will be targeted by it.

One may not have access to bank but surely, everyone has access to post office and mail carrier as well in rural areas, taking advantage of its access everywhere we may cover unbanked population under umbrella of financial inclusion.

To conclude, after launching of Indian post payment bank, concept of JUMP has emerged to push ahead work of financial inclusion, where J - Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, U- UIDAI means related to Aadhar, M- Mobile, and P- Indian post payment bank. It is quite clear that if this concept is effectively implemented it will give high jump to concept of financial inclusion. However, there are no problem in access point rather problem lies in proper maintenance of accounts which emerge because of low wage creation resulting low level of saving and finally low or no number of transactions, available evidence are conclusive enough to suggest that due to the precarious conditions of indebtedness poor people can't maintain their account.

FINANCE AND ECONOMICS THINK COUNCIL | ECONOMICS AND POLICY RESEARCH

ANTICIPATE I ANALYSIS I ARTICULATE

Layout & Design:
Harsh Singh | Nishant Kr. Upadhyay
Vikrant Singh | Ambuj Bharti
Anshuman Singh | Pawan Singh

For more updates, visit and subscribe:
www.fetc.org.in
facebook.com/fetc.org/
mail us: fetc.bhu@gmail.com

Benefactors:

Krishna Jaiswal
Aman Singh
Ratikant Bhaskar
Rahul Sarthak
Vikas Tripathi
Gopal Shukla
Krishna Dubey
Ashok Kumar
Waris Raza
Rajat Singh
Rahul Pal
Adarsh Sharma
Rajat Soni
Alok Kumar Verma
Amit Shukla
Prashant Shukla